भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2842

जिसका उत्तर 17 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है ।

26 अग्रहायण, 1947 (शक)

उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

2842. श्री राजीव राय:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मऊ और बलिया जिलों सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;
(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में उक्त कार्यक्रम के लिए कुल कितना बजटीय आवंटन किया गया है और इसका कितना उपयोग किया गया है;
(ग) वाराणसी और गोरखपुर में सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थिति क्या है;
(घ) क्या सरकार की मऊ और बलिया जिलों में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अवसंरचना स्थापित करने की योजना है; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ङ):** प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण और नागरिकों को सशक्त बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार ने जुलाई, 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था।
समग्र लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुधार करें, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करें और भारत में निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करें।
दूरदराज के गांवों में इंटरनेट की पहुंच के विस्तार से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में क्रांति लाने तक, देश ने शहरी-ग्रामीण विभाजन को काफी हद तक कम कर दिया है।
डिजिटल इंडिया में कई प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं:

- सुरक्षित दस्तावेज़ पहुंच के लिए डिजिलॉकर
- कैशलेस लेनदेन के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई)
- मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग)
- वैक्सीन प्रबंधन के लिए कोविन, और
- खरीद में पारदर्शिता के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)।

पूर्वी उत्तर प्रदेश और मऊ और बलिया जिलों सहित देश भर में सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों का विवरण इस प्रकार है: -
सामान्य सेवा केंद्र – सीएससी ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डिजिटल मोड में सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सीएससी के माध्यम से 800 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
31 अक्टूबर, 2025 तक, देश भर में (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में) 5.67 लाख सीएससी कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 4.41 लाख सीएससी ग्राम पंचायत स्तर (ग्रामीण) पर कार्य कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य में देश भर में (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में) 1.21 लाख सीएससी कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 94,000 लाख से अधिक सीएससी ग्राम पंचायत स्तर (ग्रामीण) पर कार्य कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के मऊ और बलिया जिलों में सीएससी का विवरण इस प्रकार है:-:

क्रम संख्या	जिले का नाम	कार्यात्मक सीएससी (शहरी+ ग्रामीण)	ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यात्मक सीएससी
1	बलिया	1499	1301
2	मऊ	1127	858

पीएमजीदिशा: प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
देश भर में 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल साक्षरता पहलों में से एक बन गई। यह योजना 31.03.2024 को समाप्त हो गई है।
उत्तर प्रदेश राज्य में 1.45 करोड़ लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। उत्तर प्रदेश के निर्दिष्ट जिलों की स्थिति नीचे दी गई है:

क्रम संख्या	जिले का नाम	प्रशिक्षित
1	बलिया	233409
2	मऊ	165906

फ्यूचरस्किल्स प्राइम: भारत सरकार द्वारा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) के सहयोग से उद्योग कौशल अंतर को पाटने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम। यह नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में व्यक्तियों को कुशल बनाने, पुन: कौशल प्रदान करने और कौशल बढ़ाने पर केंद्रित है।
प्लेटफॉर्म पर 500+ से अधिक पाठ्यक्रम और 2000+ डिजिटल प्रवाह मार्ग पेश किए जाते हैं। अब तक, 16.29 लाख+ उम्मीदवारों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला/प्रशिक्षण लिया है।
इसके अलावा, 340 बूटकैंप के तहत कुल 23,996 सरकारी अधिकारियों, 2367 प्रशिक्षकों और 30,053 उम्मीदवारों को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (नाईलिट) केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।
उत्तर प्रदेश में, 65000 से अधिक उम्मीदवारों को नामांकित/प्रशिक्षित किया गया है जिसमें बलिया में 600+ उम्मीदवार और मऊ जिलों में 200+ उम्मीदवार शामिल हैं।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (नाईलिट): यह डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रमों जैसे कंप्यूटर कॉन्सेप्ट (एसीसी), बेसिक कंप्यूटर कोर्स (बीसीसी), कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर कोर्स (सीसीसी) और एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स (ईसीसी) आदि पर प्रशिक्षण प्रदान करता है।
नाइलिट गोरखपुर में स्थित अपने मुख्य केन्द्र और राज्य में 3 और केन्द्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में कार्य करता है।
नाइलिट ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम, अल्पकालिक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रशिक्षण और नियमित ऑनलाइन परीक्षाएं प्रदान करके बलिया और मऊ सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में डिजिटल साक्षरता और आईटी कौशल विकास को मजबूत किया है।
नाइलिट के मऊ जिले में 76 और बलिया में 128 सुविधा केंद्र हैं। केंद्रों के इस विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से, नाईलिट ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2 लाख से अधिक उम्मीदवारों को डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया है, जिनमें से बलिया के 14157 और मऊ के 13788 उम्मीदवारों को पिछले 3 वर्षों में प्रशिक्षित किया गया है।
भारतनेट - गांवों को इंटरनेट से जोड़ना: भारतनेट परियोजना सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करती है। भारतनेट परियोजना के तहत बनाया गया बुनियादी ढांचा एक राष्ट्रीय संपत्ति है, जो सेवा प्रदाताओं के लिए गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर सुलभ है।
इसका उपयोग ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन, लीज्ड लाइनें, आदि।
अक्टूबर 2025 तक, भारतनेट परियोजना के तहत 2,14,843 ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा के लिए तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश (यूपी-ईस्ट और यूपी-वेस्ट सहित) में भारतनेट की स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य	ओएफसी पर सेवा तैयार	सैटेलाइट पर सेवा तैयार	कुल सेवा तैयार (ओएफसी+सैटेलाइट)
1	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	34263	11	34274
2	उत्तरप्रदेश (पश्चिम)	12449	23	12472

डिजिटल इंडिया एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों में कार्यान्वित कई परियोजनाएं शामिल हैं। इसके निष्पादन के लिए इन एजेंसियों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई पहलों को संयुक्त रूप से विकसित और कार्यान्वित किया जाता है।
आवंटित और उपयोग की गई निधियों का विवरण वेबसाइट https://www.digitalindia.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

आईटी क्षेत्र के विकास के लिए

भारत सरकार आईटी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दे रही है, विशेष रूप से छोटे शहरों और शहरों में। इसका उद्देश्य भारत को सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना और घरेलू मांग और निर्यात को बढ़ावा देना है।
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) प्रमुख शहरों से परे आईटी/आईटीईएस पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कई क्षेत्रों में एआई, आईओटी, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा और उद्योग 4.0 जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में स्टार्टअप, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और उत्पाद/आईपी निर्माण का समर्थन करता है।
वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित 5 एसटीपीआई केंद्र कार्य कर रहे हैं जो गोरखपुर और वाराणसी सहित सभी जिलों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं

क्र.सं.	शहर
1.	प्रयागराज
2.	कानपुर
3.	लखनऊ
4.	नोएडा
5.	मेरठ

सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) प्रमोशन स्कीम (आईबीपीएस) लॉन्च की, जिसका उद्देश्य छोटे शहरों/कस्बों में रोजगार के अवसर पैदा करना और आईटी/आईटीईएस उद्योग का वितरण करना था, इसके लिए बीपीओ/आईटीईएस संचालन स्थापित करने पर प्रोत्साहन दिया गया, जिसकी कुल लागत ₹493 करोड़ थी।
इस योजना ने पूंजीगत और परिचालन व्यय के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के रूप में 1 लाख रुपये प्रति सीट तक 50% वित्तीय सहायता प्रदान की।
इसके अतिरिक्त, इस योजना में स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने, महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार को प्रोत्साहित करने आदि इकाइयों को विभिन्न विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। इस योजना की अवधि समाप्त हो चुकी है।
इस योजना के तहत, 227 इकाइयों ने देश के 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 93 छोटे शहरों/कस्बों में बीपीओ/आईटीईएस परिचालन स्थापित किया है और उत्तर प्रदेश राज्य में 870 सहित 52,514 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया है।

*****